ई-संदेश

9 अक्टूबर, 2025 | अंक 174

सात दिन – सात पृष्ठ

केन्द्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 08 अक्टूबर, 2025 को अयोध्या स्थित बृहस्पति कुण्ड स्थल पर दक्षिण भारत के प्रमुख संतों की प्रतिमाओं का अनावरण करते हुए।

- प्रदेश सरकार वर्षा जल संचयन और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की दिशा में लगातार कदम उठा रही : मुख्यमंत्री
- प्रदेश के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री
- विकास परियोजनाओं को समग्रता के साथ आगे बढ़ाया जाए: मुख्यमंत्री
- शहरों में होने वाले विकास कार्य नियोजित ढंग से और समन्वित रूप में किए जाएं :मुख्यमंत्री
- संस्कृत में विशिष्ट शोध और उच्च अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी: मुख्यमंत्री
- स्वच्छता का अभियान स्वच्छ, सशक्त और समर्थ भारत की आधारशिला: मुख्यमंत्री
- प्रदेश को देश के फूड बास्केट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए अनेक सम्भावनाएं मौजूद: मुख्यमंत्री
- दक्षिण भारत के पूज्य संतों ने सदैव से उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का कार्य किया है :मुख्यमंत्री

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

प्रदेश सरकार वर्षा जल संचयन और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की दिशा में लगातार कदम उठा रही : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 04 अक्टूबर, 2025 को यहां लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (लघु सिंचाई) के कार्यों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल संकट आज हमारी सामूहिक चिन्ता का विषय बन चुका है। चेक डैम, तालाब और ब्लास्टकूप वर्षा जल को रोककर धीरे-धीरे उसे भूमि में समाहित होने देते हैं। यह केवल स्थानीय प्राथमिकता नहीं है बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि चेक डैम, तालाब और ब्लास्टकूप केवल पानी रोकने की व्यवस्था नहीं बल्कि समेकित जल प्रबन्धन है, जो बड़े बांधों की तुलना में काफी किफायती है। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की तर्ज पर जनांदोलन बनाते हुए चेक डैम, तालाब और ब्लास्टकूप का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थानीय, बरसाती नदी-नालों में विभाग द्वारा 6,448 चेकडैमों का निर्माण किया जा चुका है। प्रत्येक चेकडैम से औसतन 20 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता विकसित होती है। इस प्रकार निर्मित चेकडैमों से कुल 1,28,960 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 10 हजार हेक्टेयर मीटर से अधिक भूजल रिचार्ज हो रहा है। इन प्रयासों से अन्नदाता किसान वर्ष में दो से तीन फसल उत्पन्न करने में सक्षम हुए हैं।वर्षा जल संचयन और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से अब तक 1,002 चेकडैमों की डी-सिल्टिंग और मरम्मत कर उनकी क्षमता में वृद्धि की गई है। इसी तरह प्रदेश के 01 से 05 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 16,610 तालाबों में से 1,343 तालाबों का पुनर्विकास और जीर्णोद्धार किया गया है, वहीं वर्ष 2017-2025 तक 6192 ब्लास्ट कूप के माध्यम से 18576 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई है।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक वर्ष वर्षाकाल से पूर्व अर्थात् 01 अप्रैल से 15 जून तक कुम्हारों को तालाब से निःशुल्क मिट्टी निकालने की छूट दी जाए, ताकि तालाब रिचार्ज के लिए तैयार हो सकें। बरसात के पश्चात इन्हें मत्स्य पालन और सिंघाड़ा उत्पादन के लिए उपयोग में लाकर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष बल देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में 100 वर्ग मीटर से बड़े सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। शहरी और ग्रामीण दोनों

क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए यह कदम निर्णायक साबित होगा।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 तक प्रदेश में 82 अतिदोहित और 47 क्रिटिकल क्षेत्र थे। सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2024 में 50 अतिदोहित और 45 क्रिटिकल क्षेत्र रह गए हैं, यह संतोषजनक स्थिति है। इस दिशा में और तेजी लाकर आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों को पूरी तरह सामान्य श्रेणी में लाने का प्रयास होना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान ने वृक्षारोपण को जनांदोलन का रूप दिया है, वैसे ही चेकडैम और तालाब निर्माण का कार्य भी सामूहिक प्रयासों से बड़े स्तर पर संचालित किया जाए। यह न केवल जल संकट से निपटने में सहायक होगा, बल्कि प्रदेश की कृषि, मत्स्य पालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक जनपद में तालाबों, ब्लास्टकूपों और चेकडैमों का फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन कराया जाए। जनता को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अभियान चलाया जाए। जल संरक्षण और भूजल रिचार्जिंग को लेकर प्रदेश सरकार का संकल्प अटल है और इसे समाज की भागीदारी से एक सफल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रदेश के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 04 अक्टूबर, 2025 को यहां लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नलकूपों का प्राथमिकता के आधार पर जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण किया जाए। इससे सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, किसानों की लागत घटेगी और उन्हें आधुनिक तकनीक आधारित सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश देते हुए कहा कि नलकूपों के आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता न किया जाए। नलकूपों के आधुनिकीकरण और जल संरक्षण की इन पहलों से आने वाले

समय में राज्य का कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी।

नलकूपों से पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाए और वाटर कंजर्वेशन की समुचित व्यवस्था की जाए। इस कार्य के लिए वर्षा का मौसम सर्वाधिक उपयुक्त है। इससे भूगर्भीय जल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी और डार्क जोन वाले क्षेत्रों में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री जी ने सरयू नहर, बाण सागर तथा मध्य गंगा जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की कमियों को दूर करने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के सशक्त क्रियान्वयन से ग्रामीण और शहरी इलाकों में पानी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित होगा।

उन्होंने तराई क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि जलाशयों को डीसिल्ट कर, उन्हें पुनर्जीवित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि कटान रोकने के लिए सिल्ट का उपयोग किया जाए।

विकास परियोजनाओं को समग्रता के साथ आगे बढ़ाया जाए: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 04 अक्टूबर, 2025 को यहां लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यां की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के अवस्थापना और शहरी विकास कार्यों को नए स्तर पर ले जाया जाए। वरिष्ठ अधिकारी धरातल पर उतरकर परियोजनाओं की प्रगति देखें और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यों को आगे बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान बनाते समय चयन प्रक्रिया को वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाएं, ताकि योजनाएं व्यवहारिक तौर पर धरातल पर उतर सकें। उन्होंने अधिकारियों को अल्प अवधि, मध्य अवधि और दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर विकास परियोजनाओं को समग्रता के साथ आगे बढ़ाने को कहा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरठ, कानपुर एवं मथुरा-वृन्दावन के समग्र विकास हेतु 1,833 करोड़ रुपये की लागत से 38 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें मेरठ में 11, कानपुर में 13 और मथुरा वृन्दावन में 14 परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि हर प्रस्ताव को स्थानीय स्तर पर सर्वे और अध्ययन के बाद ही अंतिम रुप दिया जाए, ताकि योजनाएं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों और जनता को इनका वास्तविक लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री जी ने राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित 28 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के सम्बन्ध में कहा कि राजधानी में संचालित विभिन्न परियोजनाओं को आपस में जोड़ने से आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रीन कॉरिडोर और अन्य अवस्थापना परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधि निवेश ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए, ताकि कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे किए जा सकें।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये कि सभी परियोजनाओं को विभागीय कन्वर्जेंस के माध्यम से धरातल पर उतारा जाए। विकास प्राधिकरण ऐसी परियोजनाएं तैयार करें, जो राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल साबित हों और प्राधिकरण की आय का स्रोत भी बनें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास प्राधिकरण केवल निर्माण तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए नवाचार करें।

मुख्यमंत्री जी ने विकास प्राधिकरणों को अपने बॉन्ड जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे न केवल प्राधिकरणों की आय बढ़ेगी, बल्कि उनकी कार्यकुशलता और पारदर्शिता पर जनता का विश्वास भी सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण अपनी योजनाओं को ब्राण्ड बनाएं और अन्य राज्यों के लिए

उदाहरण प्रस्तुत करें।
मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये कि प्राधिकरण किसी भी भवन का नक्शा तभी पास करें, जब उसमें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो। भविष्य की आवश्यकताओं और जल संकट की गंभीरता को देखते हुए यह व्यवस्था अनिवार्य है और इसे हर हाल में लागू कराया जाए। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पी0पी0पी0 मॉडल पर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जाए। साझा राजस्व के आधार पर प्राधिकरण भूमि उपलब्ध कराए और निवेशक इसका निर्माण व संचालन करें। इससे प्रदेश को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी और निवेश का वातावरण और बेहतर होगा।
मुख्यमंत्री जी ने सभी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि योजनाएं ऐसी हों, जो केवल आज की आवश्यकताओं को नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों की जरूरतों को भी पूरा करें। उन्होंने कहा कि अवस्थापना विकास को केवल निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और जनता की सुविधा से सीधे जोड़ना चाहिए। विकास कार्यों में पारदर्शिता, जनता की भागीदारी और दीर्घकालिक दृष्टि का समावेश होना चाहिए। यही उत्तर प्रदेश को विकसित भारत के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगा।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से 05 अक्टूबर, 2025 को राजभवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल जी को श्री अनिल फिरोजिया द्वारा लिखित पुस्तक "विवेकानंद और मोदी" भेंट की।

शहरों में होने वाले विकास कार्य नियोजित ढंग से और समन्वित रूप में किए जाएं :मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 04 अक्टूबर, 2025 को यहां लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में नगर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरों में होने वाले विकास कार्य नियोजित ढंग से और समन्वित रूप में किए जाएं। अलग-अलग विभागों द्वारा अलग-अलग कार्य करने से योजनाओं में अनावश्यक देरी होती है। इसलिए सभी विभाग मिलकर साझा कार्ययोजना बनाएं और समयबद्ध ढंग से इनका क्रियान्वयन करें।

मुख्यमंत्री जी ने मलिन बस्तियों में विकास पर विशेष बल देते हुए कहा कि यहां साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, सड़क कनेक्टिविटी और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन बस्तियों के विकास की जिम्मेदारी ठेकेदारों को न दी जाए, बल्कि नगर निकाय स्वयं इसकी जिम्मेदारी उठाएं और समय-समय पर उसकी मॉनिटरिंग करें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल निकासी व्यवस्था (ड्रेनेज सिस्टम) को और मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रत्येक शहर में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जिससे भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रेनेज सिस्टम के सुधार और नई व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि नागरिकों को बरसात के समय किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मलिन बस्तियों और पब्लिक प्लेसेज़ पर अधिक से अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाए। इन सामुदायिक शौचालयों में नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था हो। नगर निकायों से जुड़े नए गांवों में भी मूलभूत सुविधाएं शीघ्र सुनिश्चित की जाए, जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। लापरवाही की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी की योजनाओं को इस तरह तैयार किया जाए, जिससे शहर का समग्र विकास हो और राजस्व वृद्धि भी सुनिश्चित हो। शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, रेस्टोरेंट और ऑडिटोरियम जैसे प्रोजेक्ट्स को पी0पी0पी0 मॉडल पर विकसित करें। स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्होंने नियमित कूड़ा उठान और उसके निस्तारण को सुनिश्चित करने के साथ-साथ ठोस और गीले कचरे को अलग करने के लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री जी ने बिना मानक और नगर निकायों की अनुमति के बिना विकसित होने वाली कॉलोनियों और बस्तियों पर प्रारम्भिक स्तर पर ही रोक लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी अनधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि शहरों की नियोजित संरचना बनी रहे। उन्होंने नगर विकास से जुड़ी सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग पर बल देते हुए कहा कि योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

संस्कृत में विशिष्ट शोध और उच्च अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 06 अक्टूबर, 2025 को जनपद वाराणसी में श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय में काशी अन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित सिलाई-कढ़ाई एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र के 14वें सत्रान्त पर छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र, लैपटॉप एवं छात्राओं को सिलाई मशीन वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्री अन्नपूर्णा मठ मंदिर द्वारा अनेक लोकोपकारी प्रकल्प प्रारम्भ किये गये हैं। श्री अन्नपूर्णा मठ मंदिर द्वारा संचालित श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय विगत 108 वर्षों से भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं प्रसार में निरन्तर सक्रिय है। आज यहां 250 से अधिक बेटियों को सिलाई मशीन तथा अनेक छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण के उपरान्त लैपटॉप प्रदान किये गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संस्कृत पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के रहने और खाने की व्यवस्था के लिए सरकार अनुदान की व्यवस्था करने जा रही है। संस्कृत में विशिष्ट शोध और उच्च अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी। दुनिया के प्राचीनतम ज्ञान की धरोहर संस्कृत में सुरक्षित है। संस्कृत विज्ञान के साथ दिव्य ज्ञान की भी भाषा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संस्कृत में वेद और व्याकरण दुनिया को भारत की एक विशिष्ट देन है। भारत के तक्षशिला में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खोला गया था। व्याकरण के आद्य रचयिता भगवान पाणिनि इस विश्वविद्यालय की देन हैं। भगवान पाणिनि के व्याकरण सूत्रों में व्याकरण के साथ-साथ उस समय के इतिहास व परम्परा के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। यह भारत की देन है। कल महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। महर्षि वाल्मीकि ने व्यावहारिक संस्कृत में दुनिया का पहला महाकाव्य रचा था।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति ने नारी सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलम्बन को सदैव महत्व प्रदान किया है। भारतीय संस्कृति सदैव 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' भाव की आग्रही रही है। सनातन संस्कृति हमेशा मातृ शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करती रही है। 'माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या' भाव के साथ हम सभी धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम दुनिया की सबसे पवित्र नदी गंगा को मां के रूप में मानकर उसकी अराधना करते हैं। चराचर जगत की आदिशक्ति मां भगवती हैं। इस जगत में मानव, जीव-जन्तु आदि को मां अन्नपूर्णा की कृपा से भोजन प्राप्त होता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से नारी सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलम्बन की दिशा में अनेक कार्य किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नारी गरिमा को महत्व प्रदान करते हुए बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ, हर घर शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अनेक योजनाएं चलाई है। देश में 04 करोड़ तथा प्रदेश में 60 लाख गरीब परिवारों को आवास की सुविधा प्राप्त हुई है। देश में 12 करोड़ गरीबों के घर में एक-एक शौचालय का निर्माण किया गया है। देश में 10 करोड़ महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क रसोईगैस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं। इससे महिलाओं को ईंधन से होने वाले धुंए से मुक्ति मिली है। काशी में पाइप लाईन से गैस की सप्लाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां आवास है, वहीं पर मालिकाना हक प्रदान करने के लिए देश में 03 करोड़ परिवारों की महिला सदस्यों को घरौनी का अधिकार दिया गया है। महिला सदस्य अब भूमि पर ऋण लेकर व्यवसाय आदि कार्य कर सकती है। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा कौशल विकास सहित जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। श्री अन्नपूर्णा मठ मन्दिर द्वारा प्रति वर्ष 250 बालिकाओं को प्रशिक्षण देकर सिलाई मशीन प्रदान की जाती है, जिससे यह बालिकाएं अपने परिवारों का भरण-पोषण करने में सक्षम हुई हैं।

स्वच्छता का अभियान स्वच्छ, सशक्त और समर्थ भारत की आधारशिला: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 06 अक्टूबर, 2025 को जनपद वाराणसी में स्वच्छता मित्रों के सम्मान समारोह में प्रतिभाग कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री जी ने देश में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था, जिसमें स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथों में झाड़ू ली थी। एक ओर जहां इस अभियान के माध्यम से स्वच्छता में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर लोगों को गंदगी से होने वाली बीमारियों से राहत मिली। स्वच्छता कर्मी स्वच्छता के आधार व स्वच्छता मित्र हैं। यह स्वच्छता के लिए आग्रह करते हैं तथा स्वयं के स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। हमें भी संकल्पित होना है कि अपनी मातृभूमि को गंदा नहीं होने देंगे, किसी भी कलुषित मानसिकता का शिकार नहीं होने देंगे तथा कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलने देंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत भारत में 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का अभियान शुरू किया गया। शौचालय का निर्माण केवल शौचालय का निर्माण मात्र ही नहीं, बल्कि नारी गरिमा की रक्षा करना तथा स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को आग्रही बनाना था। वर्ष 2014 से पूर्व बारिश के मौसम में गांव में पैदल भी नहीं जा सकते थे। गांव के रास्तों में बदबू आती थी। वर्ष 2014 के पश्चात लाए गए परिवर्तन के परिणामस्वरुप आज हमारे गांव साफ-सुथरे हो गये हैं, जिससे भारत के बारे में लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। आज दुनिया भारत के बारे में अच्छा सोचती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के उपचार के लिए आयुष्मान भारत योजना दी। इससे लोगों के घरों में बचत भी हुई। स्वच्छता का अभियान स्वच्छ भारत के साथ-साथ सशक्त और समर्थ भारत की आधारशिला है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया। उन्होंने इसे शताब्दी संकल्प अभियान के साथ जोड़ा। समर्थ, विकसित और आत्मनिर्भर भारत ही सशक्त भारत बनेगा। दुनिया का कोई भी देश भारत की ओर आंखें टेढ़ी करके नहीं देख सकेगा। ऐसे सशक्त और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प प्रत्येक देशवासी का है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 17 सितंबर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, 25 सितंबर अंत्योदय के प्रणेता पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी तथा 02 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चलाया गया। सेवा पखवाड़ा के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर तय कार्यक्रमों की श्रृंखला में 03 महीने पहले से 75 दिन के वार्ड प्रवास अभियान चलाया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और जब जनप्रतिनिधि मौके पर जाकर जनता की समस्याओं को सुनता है, तो समस्या के समाधान का रास्ता वहीं पर निकल आता है। जनप्रतिनिधियों द्वारा 70 दिन के अभियान के दौरान प्रत्येक वार्ड में कार्यकर्ताओं के साथ जाना तथा चौपाल लगाने का कार्य अद्भुत रहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वार्ड प्रवास कार्यक्रम नई प्रेरणा के साथ नया प्रयोग है। इस दौरान 33 हजार से भी अधिक जन समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। इसके माध्यम से लोगों को समाधान के लिए एक मंच प्राप्त हुआ। कार्यकर्ताओं, नगर निगम के पार्षदों व अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा। वार्ड प्रवास कार्यक्रम के दौरान इनके समाधान में कार्यकर्ताओं को स्वच्छता कर्मियों के साथ संवाद स्थापित करने का अवसर मिला।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्द ही स्वच्छता कर्मियों के खातों में सीधे 16 से 20 हजार रुपए की धनराशि हस्तांतरित करने का आदेश भी जारी होने वाला है। अब कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। सरकार जल्द ही सभी स्वच्छता कर्मियों को 05 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज हेतु आयुष्मान कार्ड की सुविधा देने जा रही है। उन्होंने कहा कि कार्य करने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा, उतना स्वस्थ रहेगा। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी को मेहनतकश लोगों ने मात दी।

प्रदेश को देश के फूड बास्केट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए अनेक सम्भावनाएं मौजूद: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 06 अक्टूबर, 2025 को अन्तरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केन्द्र (आइसार्क), जनपद वाराणसी में कृषि विभाग की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश को वर्ष 2030 तक वैश्विक फूड बास्केट बनाने के लिए विचार विमर्श के उद्देश्य से आयोजित 'डायरेक्ट सीडेड राइस कॉन्क्लेव' को सम्बोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खेती-किसानी आज की नई देन नहीं है। भारत के उपनिषद् हजारों वर्षों की ऋषि परम्परा के आध्यात्मिक ज्ञान की एक बड़ी धरोहर है। भारत की भूमि अत्यन्त उर्वरा है। भौगोलिक दृष्टि से दुनिया में भारत सातवें स्थान पर है।

दुनिया के कुल भू-भाग में मात्र 10 प्रतिशत भू-भाग ही कृषि योग्य है। भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक कृषि योग्य उर्वरा भूमि है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे अधिक सौभाग्यशाली है कि भारत की कुल भूमि का हमारे पास मात्र 11 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। हमारे पास प्रदेश को देश के फूड बास्केट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए अनेक सम्भावनाएं मौजूद हैं। इसी प्रदेश में 11 फीसदी भूभाग में हम देश के 21 प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित चार कृषि विश्वविद्यालय, भारत सरकार के दो कृषि विश्वविद्यालय, एक निजी कृषि विश्वविद्यालय और 89 कृषि विज्ञान केन्द्र अब तक सहयोग कर रहे हैं। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वाराणसी में 'इरी' का सेण्टर खुला। इसने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उत्तर प्रदेश सहित देश के लिए किया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसके पास सर्वाधिक कृषि विश्वविद्यालय भी हैं। पांचवा कृषि विश्वविद्यालय हम बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही, हमारे पास वाराणसी में राइस तथा आगरा में पोटैटो के दो अन्तरराष्ट्रीय शोध केन्द्र भी प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किये। इण्टरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का दक्षिण एशिया केन्द्र, वाराणसी वर्ष 2018 से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत में संभावनाएं पहले से थीं। पहले केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का उपयोग भारत में नहीं होता था। कम लागत में अधिक उत्पादन आज की आवश्यकता है। हम इस दिशा में कौन से प्रयास कर सकते हैं। भारत के प्राचीन वैज्ञानिक इसके लिए क्या करते थे। हम आज उसे फिर से किस प्रकार अपना सकते हैं। पहले हम अपने यहां डी0एस0आर0 पद्धति लागू करते थे, क्योंकि इसमें कम पानी लगता है और उत्पादन भी ठीक होता था। जब भी हम इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को छोड़ देंगे, तो हमारे आगे बढ़ने की संभावना उतनी ही क्षीण हो जाएगी। यही हमारे साथ हुआ। आज हमें अपने सामने मौजूद चुनौतियों का सामना करते हुए कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि काला नमक चावल 3,000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध का प्रसाद है। भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में हम इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 80 प्रतिशत से अधिक भूमि सिंचित है। हमारे यहां अत्यंत उर्वरा भूमि है, सिंचाई और धूप की भी प्रचुरता यहां पर है। वर्ष के 12 माह में से 11 माह हमें बेहतर धूप मिल जाती है। अच्छी बरसात भी होती है। हमारे पास ग्राउण्ड वॉटर भी है और सरफेस वॉटर भी है। हर पांच कोस में यहां एक नदी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश हर प्रकार से धन-धान्य बाहुल्य क्षेत्र है। प्रदेश में दलहनी फसलों और गन्ना तथा आलू सहित सभी प्रकार की फसलों के लिए बहुत उपयोगी भूमि है। उत्तर प्रदेश में लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि में धान और 100 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं की खेती होती है। 29 लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ना की खेती भी की जाती है। दलहन और तिलहन में भी एक बड़ा क्षेत्रफल प्रदेश में मौजूद है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 1950 की तुलना में वर्ष 2023 में हमने खाद्यान्न उत्पादन में पांच गुना की वृद्धि की है। धान, गेहूं, गन्ना, आलू, दलहन में उड़द, मूंग, अरहर, चना, मटर, मसूर और तिलहन में सरसों, मूंगफली की बेहतरीन खेती उत्तर प्रदेश में हो रही है और इनका अच्छा उत्पादन भी हो रहा है। हमें इस दिशा में आगे लगातार प्रयास करने चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगरा में इण्टरनेशनल पोटैटो सेण्टर शीघ्र संचालित होना चाहिए। यदि आवश्यकता हो, तो कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तात्कालिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहां उपलब्ध करवाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पूरी मदद करेगी। प्रदेश में अच्छी खेती और क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने के लिए अच्छे बीज चाहिए। हम लखनऊ में 250 एकड़ क्षेत्रफल में पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क की स्थापना कर रहे हैं। यदि हम मिलकर किसानों को तकनीक दे सकें, उन्हें समय पर अच्छे बीज उपलब्ध करा सके और समय पर उन्हें सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करवा सकें, तो उत्तर प्रदेश आज जितना खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है, इससे तीन गुना अधिक उत्पादन कर सकता है। यह सामर्थ्य उत्तर प्रदेश की धरती में है।

यदि उत्पादन की क्षमता को बढ़ाएंगे और लागत को कम करेंगे, तो उत्तर प्रदेश वर्ष 2029-30 में 01 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी अवश्य बनेगा। इसमें एग्रीकल्चर की भी बड़ी भूमिका होगी।

मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इरी और सी0आई0पी0 के इण्टरनेशनल सेण्टर की भांति ही अन्य सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स विकसित करके हम अपने अन्नदाता किसानों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद कर पाएंगे। फिर कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट ना बन जाए। भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम पूरा योगदान देंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने विगत 27 मई से 12 जून तक भारत के कृषि वैज्ञानिकों से 'लैब टू लैण्ड' कार्यक्रम के माध्यम से फील्ड में उतरकर किसानों से जुड़ने का आह्वान किया था। 'लैब टू लैण्ड' के कार्यक्रम के साथ हमारे सभी वैज्ञानिक जुड़ेंगे, तो उसके बेहतरीन परिणाम आएंगे। हमारा डेमोन्स्ट्रेशन का आधार हमारी लैब नहीं, बल्कि कृषि भूमि होगी। इससे हम अन्नदाता किसान को अधिक से अधिक फैसिलिटेट कर पाएंगे।

दक्षिण भारत के पूज्य संतों ने सदैव से उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का कार्य किया है :मुख्यमंत्री

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 08 अक्टूबर, 2025 को अयोध्या स्थित बृहस्पति कुण्ड स्थल में दक्षिण भारत के प्रमुख संतों श्री पुरंदर दास, श्री त्यागराजा और श्री अरुणाचल कवि की प्रतिमाओं का अनावरण तथा बृहस्पति कुण्ड के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दक्षिण भारत के संतों के योगदान को बहुत प्रभावी ढंग से हमारे सामने रखा है। अयोध्या आस्था का केन्द्र तथा भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। श्रीराम नगरी अयोध्या आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केन्द्र बन रही है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे दक्षिण भारत के हर घर में भगवान श्रीराम का प्रभाव देखने को मिलता है। आज का दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अपनी हर सांस में भगवान श्रीराम का नाम जपने वाले तीन संतों को अयोध्या में स्थान मिला है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें पूरा सहयोग है। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हमारी भावनाएं एक ही हैं और वह हैं 'एक भारत श्रेष्ठ भारत'।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन पूज्य संतों ने दक्षिण भारत में 15वीं सदी से 18वीं सदी तक श्री रामभक्ति के प्रचार-प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आज उनकी प्रतिमा उनके आराध्य के श्रीचरणों में बृहस्पति कुण्ड स्थल पर स्थापित हुई है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अभियान को आगे बढ़ाने का अवसर भी है। इन पूज्य संतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की दृष्टि से आज का यह समारोह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका माध्यम केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी बनी हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि से देश में नेक्स्ट जेनरेशन जी0एस0टी0 रिफॉर्म के माध्यम से 140 करोड़ देशवासियों को बड़ी राहत दी है। पर्व और त्योहारों के अवसर पर लोगों के मन में इससे बड़ा उत्साह बना है। बाजार में एक नई मजबूती देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री जी ने केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री का नेक्स्ट जेनरेशन जी0एस0टी0 रिफॉर्म के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दक्षिण भारत के पूज्य संतों ने सदैव से उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का कार्य किया है। जगद्गुरु शंकराचार्य ने दक्षिण भारत के केरल से निकलकर देश के चार कोनों में चार पीठों की स्थापना की थी और वैदिक धर्म को मजबूती के साथ स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज भी हम जगद्गुरु शंकराचार्य के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर में दक्षिण दिशा में बनने वाला द्वार संख्या-11 जगद्गुरु शंकराचार्य के नाम पर जाना जाएगा। इसी प्रकार सुग्रीव किला की ओर से श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर में प्रवेश करने पर पड़ने वाले द्वार को जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के नाम पर जाना जाएगा। दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित द्वार संख्या-3 को जगद्गुरु मध्वाचार्य जी के नाम पर जाना जाएगा। उत्तर दिशा में स्थित द्वार को जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी के नाम पर जाना जाएगा। हमारे पूज्य संतों, जिन्होंने भारत की संस्कृति, परम्परा व दर्शन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उनके नाम पर यह द्वार उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का माध्यम है। यह प्रधानमंत्री जी के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान को आगे बढ़ाने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का एक नया प्रयास है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित